भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1551
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।
9 श्रावण, 1946 (शक)

डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास

1551. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पहल को किस प्रकार प्रोत्साहन दे रही है;
(ख) क्या सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए पहलें की हैं; और
(ग) प्रौद्योगिकीय नवाचार और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योगों के हितधारकों और शिक्षाविदों के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): डिजिटल इंडिया, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डिजिटल सशक्तिकरण में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन, क्लाउड पर सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की उपलब्धता, भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता, सहभागितापूर्ण शासन के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी अधिकारों की पोर्टेबिलिटी शामिल है।

डिजिटल विभाजन को मिटाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए विभिन्न डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम जैसे: बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी) और बेसिक कोर्स इन आईटी (बीसीआईटी) की पेशकश की जा रही है। ये पाठ्यक्रम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलेट) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के साथ मामूली लागत पर उपलब्ध हैं।

ii. भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता (प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना लागू की है। 31 मार्च 2024 तक लगभग 7.35 करोड़ उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 6.39 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.78 करोड़ उम्मीदवारों को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया। इस

योजना को सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश भर में 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 4.39 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लागू किया गया था।

iii. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। 26 जुलाई 2024 तक लगभग 13.22 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 5.97 लाख उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई योजना के तहत प्रमाणित किया गया है।

iv. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलेट), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी अपने 52 केंद्रों के साथ-साथ 700 से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थानों और 9500 से अधिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से विभिन्न डिजिटल साक्षरता/कौशल कार्यक्रम प्रदान कर रही है। पिछले 3 वर्षों में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न दीर्घकालिक औपचारिक और अनौपचारिक, लघु अवधि पाठ्यक्रमों में नाइलेट द्वारा कुल 25,50,555 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/कुशल बनाया गया है।

v. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और देश भर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुविधा के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निःशुल्क है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। 22 जुलाई 2024 तक दीक्षा का उपयोग करके 549.71 शिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इसने 17.77 करोड़ कोर्स नामांकन और 14.24 करोड़ कोर्स पूर्ण किए हैं। आज तक 1.71 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं और इनमें से 25.36 लाख उपयोगकर्ता उत्तर प्रदेश से हैं। शिक्षकों द्वारा इस प्लेटफॉर्म का काफी उपयोग किया जाता है।

vi. स्वयं प्रभा-32 निःशुल्क डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समर्पित हैं। स्वयं प्रभा प्रतिदिन कम से कम (4) घंटे के लिए नई सामग्री होस्ट करता है। इसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। चैनल भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष एप्लीकेशन्स और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बिसाग-एन) से जुड़े हुए हैं जो एमईआईटीवाई का एक संस्थान है। यह सामग्री, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम (एनपीटीईएल), आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा प्रदान की जाती है।

vii. देश में कागज रहित शासन की सुविधा प्रदान करने तथा आम नागरिकों को अपने सार्वजनिक दस्तावेजों को आसानी से संग्रहित करने और साझा करने में सहायता करने के लिए डिजिलॉकर की शुरुआत की गई है। डिजिलॉकर से 30 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े हैं तथा इसमें 675 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

viii. नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप (उमंग) 200 से अधिक विभागों से 2000 से अधिक सरकारी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। ये सेवाएँ देश भर के नागरिकों के लिए 23 भाषाओं में उपलब्ध हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म निःशुल्क है और किसी के भी उपयोग के लिए खुला है।

ix. आम नागरिकों को व्यक्तिगत और प्रोफाइल तरीके से जानकारी प्रदान करने के लिए माईस्कीम योजना चालू की गई है। इस मंच पर 510 से अधिक केंद्रीय सरकार की योजनाएं और 1890 से अधिक राज्य सरकार की योजनाएं शामिल की गई हैं।

x. ई-संजीवनी, एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जो आम नागरिकों को टेली-मेडिकल परामर्श प्रदान कर रही है। 25 जुलाई 2024 तक इस प्लेटफॉर्म ने 27.28 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की है। यह प्रतिदिन 4 लाख रोगियों को सेवा प्रदान कर सकता है।

xi. लोकओएस डिजिटलीकरण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोकओएस एसएचजी सदस्यों की बचत पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है और जमीनी स्तर पर सतत आजीविका विकास के लिए आसान वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है। लोकओएस ने 10+ करोड़ परिवारों को संगठित किया है और 91.6 लाख एसएचजी को शामिल किया है।

xii. ई-ताल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर) से पता चलता है कि सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के ज़रिए औसतन 94.5 करोड़ लेनदेन की सुविधा दी जाती है। 94.5 करोड़ में से, 4.5 करोड़ दैनिक औसत लेनदेन राज्य सरकार की परियोजनाओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग देश भर में इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।

xiii. डिजिटल ग्राम परियोजना: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रयासों से, सीएससी-एसपीवी ने देश भर के 700 गांवों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से एक गांव) में शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट और वित्तीय समावेशन सेवाएं, साथ ही सरकार से नागरिक सेवाएं और व्यवसाय से नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 'डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना' को लागू किया है।

एमईआईटीवाई ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और उपाय किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

(i) टीआईडीई 2.0 योजना: प्रौद्योगिकी इंक्युबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई 2.0) योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आईओटी, एआई, ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप्स का समर्थन करने में लगे इनक्यूबेटरों को वित्तीय और

तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर राष्ट्रीय मामलों के सात विषयगत क्षेत्रों में टेक-स्टार्टअप्स को व्यापक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में इंक्युबेशन गतिविधियों को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से तीन-स्तरीय संरचना से 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना की परिकल्पना पांच वर्षों की अवधि में लगभग 2,000 तकनीकी स्टार्ट-अप को इंक्युबेशन सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

(ii) एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच): पूरे भारत में डीप टेक स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के लिए एक नोडल इकाई 'एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब' (एमएसएच) की स्थापना एमईआईटीवाई के तहत की गई है। एमएसएच इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को उनकी स्केलेबिलिटी, मार्केट आउटरीच आदि में सुधार करने में सहायता कर रहा है और इसने विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी भी स्थापित की है जिससे नवाचार और तकनीकी उन्नति पर आधारित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमएसएच ने 4550 से अधिक स्टार्टअप, 460 इनक्यूबेटर, 452 मेंटर, 22 एक्सेलेरेटर और 43 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों का एकीकरण किया है, जिनमें वर्तमान की और कठिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव उत्पादों / सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 143 चुनौतियों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

(iii) जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स): एमईआईटीवाई ने टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स की खोज, समर्थन, विकास और सफल बनाने के लिए 5 साल के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जेनेसिस की परिकल्पना की है, जिसमें समावेशिता, पहुंच, सामर्थ्य के सिद्धांतों के आधार पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, सरकार और कॉरपोरेट्स के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार और आर्थिक आउटपुट में वृद्धि हो सके। जेनेसिस विशेष रूप से खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप बनाने के लिए तकनीकी इकोसिस्टम को और बढ़ाने और बनाए रखने की परिकल्पना करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप्स पर प्रभाव डालना और उन्हें समेकित करना है ताकि समान स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

****